

मजदूर एकता लहर



हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार



ग़ंथ-36, अंक - 5, 6

मार्च 1-15, 2022, मार्च 16-31, 2022 (संयुक्त अंक)

पाक्षिक अख़बार

कुल पृष्ठ-10

चुनावों का इस्तेमाल सरमायदारों के राज को स्थिर करने के लिए

फरवरी-मार्च 2022 में जिन पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे बताते हैं कि शासक वर्ग ने अपना तात्कालिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व वाले सरमायदार वर्ग ने पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश सहित बाकी सभी चार राज्यों में भाजपा को जिताया है।

ये चुनाव ऐसे समय पर हुए हैं जब मजदूर, किसान और अन्य मेहनतकश अभूतपूर्व स्तर की आर्थिक कठिनाई, बेरोजगारी और आजीविका की असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सी.ए.ए. के विरोध में प्रदर्शन, आम हड़तालों में मजदूरों की बढ़ती भागीदारी, किसान आंदोलन का विकास और निजीकरण के खिलाफ़ हो रही कार्यवाहियों में विकसित होती एकता, ये सभी मिलकर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए खतरा पैदा करते हैं, जिसके ज़रिए सरमायदार राज करता है।

इन चुनावों से ठीक तीन महीने पहले, दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर किसानों को हटाने और उन्हें घर वापस भेजने में शासक वर्ग सफल रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए चुनावों

का इस्तेमाल किया गया है, ताकि वह मजदूरों तथा किसानों की आजीविका और अधिकारों पर हमला जारी रख सके और इजारेदार पूंजीपतियों के लिए अधिकतम मुनाफ़े की गारंटी दे सके। साथ ही शासक वर्ग ने इन चुनावों का इस्तेमाल भाजपा के संसदीय विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए भी किया है ताकि मजदूरों और किसानों को धोखा दिया जा सके।

पर नियंत्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेराफेरी करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं।

जहां तक इजारेदार पूंजीपतियों का सवाल है, भाजपा ने हाल के वर्षों में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया गहरे संकट में है, हिन्दोस्तानी इजारेदार घरानों के मुनाफ़ों में भारी वृद्धि हुई है।

प्रदेश के लोग कथित तौर पर योगी के नेतृत्व वाली भाजपा की सत्ता को जारी रखना चाहते हैं। कुछ अन्य लोगों का दावा है कि ये परिणाम "दक्षिणपंथी" राजनीति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। ये सभी निष्कर्ष ग़लत हैं क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में चुनावों के नतीजे जनता नहीं तय करती। चुनावों के परिणामों को शासक वर्ग निर्धारित करता है। परिणाम पूंजीपति वर्ग की योजना को दर्शाते हैं, न कि मेहनतकश जनसमुदाय की इच्छा या पसंद को।

इस सरमायदारी भ्रम कि लोग चुनाव के परिणाम तय करते हैं, इस धारणा से किये जाने वाले सभी तरह के समझौतों का हम कम्युनिस्टों को विरोध करने की ज़रूरत है। हमें इस विचार को खारिज करना चाहिए कि संघर्ष पूंजीपति वर्ग के "दक्षिणपंथी" और "वामपंथी" खेमों के बीच है। मार्क्सवादी विज्ञान ने यह स्थापित किया है कि संघर्ष सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच है।

पूंजीपति वर्ग ने वर्तमान में "सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनने" की प्रणाली को बदलकर "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" करने के इर्द-गिर्द भ्रमित करने वाली बहस शुरू

टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी और अन्य अरबपति इजारेदार पूंजीपति शासक वर्ग के मुखिया हैं। विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी शक्तियों के सहयोग से वे चुनाव के नतीजे तय करते हैं। वे भारी धन शक्ति और राज्य तंत्र पर अपने प्रभुत्व, समाचार और सोशल मीडिया पर नियंत्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेराफेरी करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं।

टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी और अन्य अरबपति इजारेदार पूंजीपति शासक वर्ग के मुखिया हैं। विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी शक्तियों के सहयोग से वे चुनाव के नतीजे तय करते हैं। वे भारी धन शक्ति और राज्य तंत्र पर अपने प्रभुत्व, समाचार और सोशल मीडिया

इस झूठे आधार पर कि वर्तमान व्यवस्था में चुनाव लोगों की राजनीतिक पसंद को दर्शाते हैं, चुनावों के परिणामों से हर प्रकार के ग़लत निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कई बुर्जुआ पत्रकारों और तथाकथित विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पंजाबी बदलाव चाहते हैं, जबकि उत्तर

शेष पृष्ठ 10 पर

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नयी दिल्ली में उत्साहपूर्ण संयुक्त कार्यक्रम

8 मार्च, 2022 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनेक महिला संगठनों ने मिलकर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।

सैकड़ों की संख्या में, स्कूल और कालेज के छात्र, फैक्ट्रियों व दुकानों में काम करने वाली महिलाएं, घरेलू कामगार, आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मी, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, वकील और अलग-अलग प्रकार की कामकाजी महिलाएं और पुरुष सभा में उपस्थित थे।

"अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद!", "महिलाओं पर हिंसा बंद करो!", "समान काम के लिए समान वेतन दो!", "बलात्कारियों को सज़ा दो!", "निजीकरण-उदारीकरण की नीतियां वापस लो!", "लेबर कोड वापस लो!", "धर्म-जाति पर हमें बांटना बंद करो!", "राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा मुर्दाबाद!", "शोषण-दमन खत्म करेंगे, नया समाज बनायेंगे!", "एक पर हमला, सब पर हमला!", "शासन-सत्ता अपने हाथ, जुल्म-अन्याय करें समाप्त!" - जुझारू नारों के इस माहौल में कार्यक्रम को संचालित किया गया। इन और अन्य



नारों के बैनरों से सभा स्थल के चारों तरफ की दीवारें सजाई गयी थीं।

इस कार्यक्रम के संयुक्त आयोजक थे - नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन (एन.एफ.आई.डब्ल्यू), अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा), पुरोगामी महिला संगठन, स्वास्तिक महिला समिति, जॉइंट विमेंस प्रोग्राम (जे.डब्ल्यू.पी.), संघर्षशील महिला केंद्र (सी.एस.डब्ल्यू), प्रगतिशील महिला संगठन, एक्शन इंडिया और जागोरी।

नौजवान कार्यकर्ताओं ने कई उत्साहपूर्ण गीत पेश किये।

सहभागी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया।

महिला मजदूरों के शोषण को और तीव्र करने वाले लेबर कोड की निंदा की गयी। लम्बे समय तक चले किसान आन्दोलन में महिलाओं की अहम भूमिका

शेष पृष्ठ 8 पर

अंदर पढ़ें

- महिलाओं का संघर्ष, शोषण मुक्त समाज की ओर 2
- अमरीका द्वारा यूक्रेन के लोगों का प्यादे के रूप में इस्तेमाल 3
- ठाणे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 4
- पार्टी का बयान - महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष को आगे बढ़ायें! 5
- किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा पर एम.ई.सी. की आठवीं मीटिंग 6
- सैनिक शासन के बीच मणिपुर में चुनाव 7
- यूनियन बनाने पर आई.टी.आई. के कर्मचारियों की बर्खास्तगी 8
- अमरीकी साम्राज्यवाद की एशिया पर हावी होने की कोशिशों की सेवा में क्वाड एक हथियार 9

To

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई-392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक- मधुसूदन कस्तूरी, ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020 email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911



WhatsApp
9868811998

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020

सरकार ने आंगनवाड़ी मजदूरों के संघर्ष पर एस्मा लगाया

10 मार्च को दिल्ली के उपराज्यपाल ने आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी मजदूरों के खिलाफ आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लगाने का आदेश दिया।

मानदेय बढ़ाने और लंबे समय से लंबित अपनी अन्य मांगों को पूरा करवाने के लिये, इस साल जनवरी से ही दिल्ली में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी मजदूर और सहायिकाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। 31 जनवरी को पूरी दिल्ली से 22,000 से अधिक आंगनवाड़ी मजदूर और सहायिकाएं बेहतर वेतन और काम करने की बेहतर स्थिति की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्यालय पर एकत्रित हुईं। "लड़ेंगे, जीतेंगे!", "नहीं डरेंगे धमकी से, खीच लेंगे कुर्सी से!" जैसे जोशीले नारे लगाते हुए, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन रोजाना जारी रखा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राजघाट पर हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी मजदूरों और सहायिकाओं ने अन्य क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं के साथ मिलकर एक विशाल प्रदर्शन में भाग लिया।

उपराज्यपाल के आदेश के बाद, आंगनवाड़ी मजदूरों की सेवाओं को "आवश्यक" सेवा घोषित करके उनकी हड़ताल को "अवैध" घोषित कर दिया गया। एस्मा के तहत अगले 6 महीनों के लिए हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी गयी है।

कम्युनिस्ट गदर पार्टी हड़ताल कर रही आंगनवाड़ी मजदूरों और सहायिकाओं पर हुए इस हमले की निंदा करती है। हम हड़ताली मजदूरों के प्रति हार्दिक समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हैं।



आंगनवाड़ी मजदूर और सहायिकाएं श्रमजीवी वर्ग के परिवारों, विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, बीमारों और वृद्धों के लिए घर-घर जाकर महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती हैं। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामुदायिक सेवाओं में शामिल है पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा और पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा। कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार द्वारा उचित सुरक्षात्मक सामग्री प्रदान नहीं किए जाने के बावजूद, आंगनवाड़ी मजदूरों और सहायिकाओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कीं।

आंगनवाड़ी मजदूरों और सहायिकाओं के कई वर्षों के लंबे और लगातार संघर्ष के बावजूद उनका जबरदस्त शोषण और उत्पीड़ित जारी है। उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती और न ही उन्हें राज्य सरकार के

वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है। उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है जो न्यूनतम वेतन से काफी कम है। वर्तमान में, दिल्ली में आंगनवाड़ी मजदूरों और सहायिकाओं को क्रमशः 9,698 रुपये और 4,839 रुपये का मामूली मानदेय मिलता है। उन्हें किसी भी प्रकार का सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलता है।

आंगनवाड़ी मजदूर अपने मानदेय को बढ़ाकर आंगनवाड़ी मजदूरों के लिए 25,000 रुपये और सहायिकाओं के लिए 20,000 रुपये करने की मांग कर रही हैं। वे अक्टूबर 2018 से जनवरी 2022 तक के 39 महीने के बकाया भुगतान की मांग कर रही हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा की गयी मानदेय वृद्धि की घोषणा के अनुसार मिलना चाहिये। वे कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस. आई.) के तहत चिकित्सा सुविधा, निश्चित काम के घंटे, सेवानिवृत्ति लाभ, सवैतनिक अवकाश, यात्रा भत्ता और भविष्य निधि (पी.एफ.) की मांग कर रही हैं। महामारी में अग्रिम पंक्ति के मजदूर बतौर, वे सरकार

से मांग कर रही हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों का चिकित्सा खर्च सरकार उठाये। उन्होंने अपनी "बेगारी" को समाप्त करने की मांग उठायी, उन्हें दासी के रूप में देखा जाता है और अधिकारियों की सनक पर उनकी नौकरी समाप्त करने की धमकी दी जाती है।

आंगनवाड़ी मजदूरों और सहायिकाओं का संघर्ष पूरी तरह से न्यायसंगत है। एक के बाद एक केंद्र और राज्यों की सरकारों ने लगातार उनकी मांगों की अनदेखी की है।

दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ (डी.एस.ए.डब्ल्यू.एच. यू.), जो संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है, कानूनी रूप से एस्मा लगाने का विरोध कर रहा है, क्योंकि आंगनवाड़ी मजदूरों को सरकारी कार्यकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है और उनकी सेवाओं को "स्वैच्छिक" माना जाता है। जबकि उन्हें अपनी हड़ताल को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा है, यूनियन ने अन्य रूपों में संघर्ष जारी रखने की घोषणा की है।

उन्होंने घोषणा की है कि यदि एस्मा को अदालत द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है, तो वे "सविनय अवज्ञा के माध्यम से एस्मा का उल्लंघन करेंगे और हड़ताल फिर से शुरू करेंगे"। वे आगामी दिल्ली नगर निगम चुनावों में केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और दिल्ली सरकार की सत्ताधारी, आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करेंगे। वे भाजपा और आप उम्मीदवारों को उनके क्षेत्रों में प्रचार करने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से विरोध करेंगे।

<http://hindi.cgpi.org/21893>

चुनावों का इस्तेमाल

पृष्ठ 1 का शेष

कर दी है। इसे वर्तमान चुनावी प्रणाली में पार्टियों के वोट शेयर और सीट शेयर के बीच के अंतर के समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है। उदाहरण के लिए 41 फीसदी वोट शेयर के साथ भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 60 फीसदी से ज्यादा सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी के पास 32 फीसदी वोट शेयर के साथ 28 फीसदी सीटें हैं। 13 फीसदी वोट शेयर वाली बहुजन समाज पार्टी के पास 1 फीसदी से भी कम सीटें हैं।

"सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनने" और "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" दोनों ही पूंजीपतियों की पार्टियों के बीच विधायी निकाय में सीटों के बंटवारे के दो अलग-अलग तरीके हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में बहस मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया में मूलभूत खामियों से लोगों का ध्यान हटाने का काम करती है।

यह केवल एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य करता है - वह है, वोट शेयर और सीट शेयर के बीच का अंतर। मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया की यह मुख्य समस्या नहीं है।

मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया में मूलभूत दोषों में निम्नलिखित शामिल हैं :

हम कम्युनिस्टों को बुर्जुआ भ्रम के साथ सभी प्रकार के सुलह का विरोध करने की जरूरत है कि लोग चुनाव के परिणाम तय कर रहे हैं। हमें इस विचार को खारिज करना चाहिए कि संघर्ष पूंजीपति वर्ग के "दक्षिणपंथी" और "वामपंथी" के बीच है। मार्क्सवादी विज्ञान ने स्थापित किया है कि संघर्ष सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच है।

- ◆ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन पार्टियों द्वारा किया जाता है, कौन उम्मीदवार हो सकता है और कौन नहीं, यह तय करने का कोई अधिकार लोगों के पास नहीं है;
- ◆ चुनाव अभियानों और मीडिया कवरेज के निजी वित्तपोषण से कुछ पार्टियों

के उम्मीदवारों और अन्य सभी उम्मीदवारों के बीच एक बहुत बड़ी विसंगति होती है;

- ◆ निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपनी पार्टी आला कमान के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि उन लोगों के प्रति जिनका उन्हें प्रतिनिधित्व करना चाहिए;

- ◆ मतदान करने वालों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को किसी भी समय वापस बुलाने का कोई अधिकार नहीं है;
- ◆ कानूनों और नीतियों पर निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित होती है, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते;

- ◆ निर्वाचित प्रतिनिधि सत्ताधारी और विपक्षी खेमों में विभाजित हो जाते हैं, कार्यकारी शक्ति एक छोटे से गुट यानी मंत्रीमंडल के हाथों में केंद्रित हो जाती है; तथा
- ◆ कार्यपालिका निर्वाचित विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती और जो निर्वाचित होते हैं वे मतदान करने वालों के प्रति जवाबदेह नहीं होते।

राजनीतिक प्रक्रिया की मूलभूत खामियों को दूर करने की मांग करना मजदूरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में है।

मजदूरों और किसानों के संघर्ष का उद्देश्य है पूंजीपति वर्ग के शासन के स्थान पर मजदूरों और किसानों का शासन स्थापित करना। तभी अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी लालच को पूरा करने की वर्तमान दिशा को बदल कर लोगों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में मोड़ा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया में बदलाव के लिए संघर्ष, जो लोगों को सत्ता में लाने की दिशा में जाएगा, इस संघर्ष का हिस्सा है।

<http://hindi.cgpi.org/21891>